PSV-PB/1Q/4.00

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत):** बिहार की महिलाओं ने, खास करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी महिलाएँ हैं, बिहार में जिनकी संख्या अभी करीब 7 लाख है, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप अच्छी सड़कें बना देंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन जब तक हमारे घर में शान्ति नहीं रहेगी, हमारे घर में लोग शराब पीते रहेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और सुनने के बाद इसे लागू किया। यह समझिए कि इसको लागू किये हुए आज 20 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस पर कई तरह के surveys आ चुके हैं। उन सब से यही पता लगता है कि इससे कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएँ होती थीं, उनमें सुधार हुआ है, एक्सिडेंट्स के जितने केसेज़ होते थे, उनमें कमी आयी है।

आप सब सहमत हैं कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, जिसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। आखिर हमारे देश के और हमारी पार्टी के जो आइकॉन हैं- गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, अम्बेडकर साहेब और कर्पूरी जी, इन सब लोगों की यह सोच रही है कि जब तक लोगों के मन में, समाज में शान्ति का माहौल नहीं रहेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर हमें एक दिन का शासन मिलेगा, तो मैं पूरे देश में शराबबंदी लागू करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे बिहार में खुशहाली आयी है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ।

महोदय, पहले जिन घरों में लोग, खास कर गरीब लोग, बड़े लोगों को छोड़ दें, शराब पीते थे और उसके साथ जो खाते थे, तो उसमें उनके करीब 200 से 300 रुपये रोज खर्च होते थे, महीने में 6,000 से 9,000 रुपये उनके खर्च हो जाते थे। आज 20 महीने में, अगर आप देखेंगे, तो पायेंगे कि एवरेज़ डेढ़ से दो लाख रुपये की बचत उनके घरों में हुई है। इसका प्रभाव आपको सामने दिखेगा। बिहार में भी छठ का पर्व होता है, यह आप सब जानते हैं। आप आज जाकर देख लीजिए। पहले क्या होता था? पहले जो कपड़े बच्चे, बच्चियाँ, महिलाएँ, पुरुष, पहनते थे, उनसे आपको पता लग जाता था कि कौन किस समाज का है, किस इनकम ग्रुप का है, लेकिन आपने इस बार देखा होगा, हम लोग तो देखते रहते हैं, तो अब उनके कपड़ों से आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन किस समाज का है। ऐसा इसलिए हुआ है कि उनके जो पैसे बचे हैं, उनमें उन्होंने माचिस नहीं लगायी है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के स्तर को सुधार करने में उनको खर्च किया है। इसका उदाहरण है, जो सर्वे हुआ है। उसे अगर आप देखें, तो पायेंगे कि जो रेडीमेड कपड़े हैं, उनकी बिक्री 45 से 50 परसेंट अधिक बढ़ी है, लोगों ने दूध की जो खपत है, उसे बढ़ाया है, मिठाइयों की खपत बढ़ी है और पहले जो बीमारियाँ होती थीं, उनमें कमी आयी है। तो यह इस बात को दर्शाता है कि इस तरह के कार्यक्रम चलाने से किस तरह का माहौल बनता है। इन्हीं महिलाओं ने फिर कहा कि नीतीश जी, शराबबंदी से तो हमें फायदा हुआ है, अब दहेजबंदी कर दीजिए, तो हमारे यहाँ और भी अच्छा माहौल होगा। इसी को लेकर हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हमारे पूरे एनडीए ने इसके साथ खड़ा होने का निश्चय लिया है। आज आप देखिए कि बिहार में यह माहौल बन गया है, कानून पहले से बना हुआ है, अपनी पार्टी के जितने भी लोग हैं, हम

लोग यह अनुरोध कर रहे हैं कि शादी में आप जो कार्ड छपवाएँ, तो उसमें यह लिखिए कि "यह जो शादी हो रही है, इसमें किसी भी दहेज का लेन-देन नहीं हुआ है।" साथ ही, बाल विवाह को रोकने के लिए भी हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि कार्ड में आप लिखिए कि "लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है।" इस तरह की जागृति अगर हम लोग पैदा कर देंगे, तो समाज में लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। कानून तो पहले से ही है। कानून अपना काम करेगा। तो इस तरह का काम हमारी सरकार में हो रहा है। इसमें हमारे केन्द्र के सभी लोगों का जो सहयोग है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

दूसरी बात, पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ASEAN के 10 शासनाध्यक्ष यहाँ आये। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। पहले बहुत मुश्किल से एक आते थे। अभी पूरे का पूरा ASEAN आपके साथ था। इसके लिए भी मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अभी वे दावोस में गये थे। पहले भी हमारे देश के प्रधान मंत्री दावोस गये हैं, लेकिन कभी बोलने का अवसर नहीं मिलता था। अभी पहली बार वे गये, वहाँ बोले और किन मुद्दों पर बोले- जो आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।

(1आर/वीएनके पर जारी)

VNK-SKC/1R/4.05

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत)** : इसके लिए भी हम प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे। आप देखिए कि आज पहली बार हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीते हैं, जिसका जिक्र अभिभाषण में भी हुआ है। हम लोगों ने किसको हराया? हम लोगों ने उस देश को हराया, जो हमारे ऊपर शासन करते थे। उनके

साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था। उनको हरा कर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीते हैं। आज विदेश में इस देश की यह जो पूरी की पूरी छवि बनी है.... और आप जानते हैं कि विदेश में छवि ऐसे नहीं बन जाती है, जब तक आपकी डोमेस्टिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक विदेश में आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप घर में मजबूत होंगे, तो बाहर भी आपकी कद्र होगी, बाहर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे।

यहां जो निर्णय लिए गए हैं, उनके चलते आज जो पहचान बनी है, उसी के चलते लोग आज हमारी बात सब जगह सुनते हैं। आप सामने देख लीजिए, जिसकी चर्चा अभिभाषण में भी की गई है और वह यह है कि इसरो के द्वारा सौवां सैटेलाइट छोड़ा गया और एक बार में 104 सैटेलाइट्स छोड़े गए। पहले जब इसरो बनी थी, तो वह किस परिस्थिति में बनी थी? जब कोल्ड वॉर का समय था, कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी ली गई और लोग यह समझते थे कि हिन्दुस्तान में इसरो का जो पूरा का पूरा मॉडल होगा, जिसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, वे लोग इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अभी हाल में इसरो के द्वारा जो सौवें multiple satellites छोड़े गए हैं, उनमें अमेरिका, फ्रांस और कनाडा के भी सैटेलाइट्स थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार इसरो में हमारे साइंटिस्टों ने काम किया है। इसके चलते हमारी पहचान बनी है। अभी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आए, तो उन्होंने हमारे तेजस प्लेन को उड़ाया। यह दर्शाता है कि पहले हमारे लोग कटोरा लेकर विदेश जाते थे कि हमको गल्ला चाहिए। आप पीएल-460 और पीएल-480 के समय को याद कीजिए। उस समय अमेरिका आपको किस तरह से डिक्टेट करता था, लेकिन आज इस देश में देखिए, हमारे किसानों ने 275 मिलियन टन

अनाज, 300 मिलियन टन सब्जी और इसी प्रकार से मछली, दूध, अंडा, शहद आदि का जो उत्पादन किया है, उसकी बदौलत अब हम लोग खाद्यान्न के मामले में किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। अब पहली क्या मांग होती है? मांग यह होती है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको बाहर से नहीं आने देना है, हम उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग करते हैं। हमारे देश के किसानों ने यह जो काम किया है, उसकी बदौलत हमारी जो पहचान बनी है, इसी के चलते आपको आज बाहर लोग इज्जत करते हैं। इस तरह का काम इस देश में हुआ है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किस बात की चर्चा की? उन्होंने अपने अभिभाषण में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा की। देश में आज़ादी मिली, तो इस आज़ादी का अहसास समाज के सभी तबकों को होना चाहिए और जो विकास हुआ है, वह सबके घर के बिल्कुल अंदर पहुंचना चाहिए। मैं तीन-चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा, जिनका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। सबसे पहली बात शौचालय के संबंध में है। आप जानते हैं, हमने बताया कि हमारी पार्टी और हम लोगों के पुरोधर लोहिया जी रहे हैं। लोहिया जी क्या कहा करते थे? वे नेहरू जी से क्या कहा करते थे? ये लोग चले गए, नहीं तो इनको बताते, वे नेहरू जी से कहा करते थे कि आप शौचालय बनवा दीजिए, हम आपका विरोध करना छोड़ देंगे। इनको मौका मिला, इन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया, लेकिन इनको याद ही नहीं रहा कि शौचालय का क्या महत्व है। कल जब लीडर ऑफ दि अपोजिशन बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपने जो शौचालय बनाए हैं, उनमें से 30 प्रतिशत ही काम करने लायक हैं। मानना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कम से कम

30 प्रतिशत तो काम कर रहे हैं, आपकी तो सोच भी नहीं थी। अगर 1947 से काम किया होता, उस समय हमारी आबादी मात्र 36 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 130 करोड़ है, तो वहां शौचालय बन गए होते और शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, बल्कि यह समझना है कि समाज में यह जो गैर-बराबरी है, उसको कम करने का यह एक बहुत बड़ा जरिया है।

(1एस/एनकेआर-एचके पर जारी)

NKR-HK/1S/4.10

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत):** पहले शौचालय कहां होते थे - सिर्फ शहरों में, बड़े-बड़े घरों में, जबकि आज गरीब आदमी के घर में भी हैं। इससे उनका जो सेंस ऑफ पज़ेशन है, डिग्निटी है, उन्हें लगता है कि आज मेरे घर में भी शौचालय है। यह एक सामाजिक बदलाव है, जिसे कहते हैं सामाजिक न्याय। देखने में शौचालय बड़ी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोग इसके प्रति आकृष्ट हुए हैं और यह बहुत अच्छी योजना है।

आज बिहार में हमारी सरकार है, एन.डी.ए. की सहयोगी पार्टी की सरकार है। हमारे यहां पहले से 'बिहार नंदन लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम' चल रहा है। अब प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है। इससे हमें नई ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

दूसरा कार्यक्रम, जिसके बारे में हमारे उधर के माननीय सदस्य कल बहुत हल्के से बोल रहे थे, वह है 'उज्ज्वला योजना'। इसके तहत हम गरीब लोगों को गैस-

कनेक्शन देते हैं। यदि उधर के माननीय सदस्य सुनते, तो उन्हें पता चलता कि जब इन्हें सरकार चलाने का मौका मिला, तो इनकी क्या सोच थी? इन्हें लगता था कि लकड़ी से खाना बनाना, कोयले से खाना बनाना, केरोसिन तेल से खाना बनाना किफायती है, लेकिन इससे जो धुआं उठता है, उससे महिलाओं और बच्चों की सेहत का बड़ा नुकसान होता है। इन्होंने कार्यक्रम चलाया था - 'स्मोकलैस चूल्हा' या धूमरहित चूल्हा। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले में अधिकारी के पद पर था। उन दिनों बीस-सूत्री कार्यक्रम का जो रिव्यू होता था, उसमें बताना पड़ता था कि आपके जिले में कितने स्मोकलैस चूल्हे बने? इनकी ऐसी सोच कभी नहीं रही कि गरीब आदमी को भी गैस कनेक्शन मिलना चाहिए। यदि ऐसी सोच उनकी होती, आप याद करें, उस समय हर सांसद के पास गैस कनेक्शन का कोटा होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी इनकी थिंकिंग थी? दूसरी तरफ, इसका इस योजना से आज लाभ हो रहा है। देश के ग्रामीण अंचल में  महिलाओं को लगता है कि उनके पास भी अब गैस का कनेक्शन है, जो पूरे का पूरा स्वच्छ ईंधन है। यह कोई छोटा काम नहीं, बल्कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री जी और केन्द्र के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। इसके तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। जब 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिल जाएगा, तो समाज में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा।

इसके बाद मैं बिजली की तरफ आता हूं। जब हमारे विपक्ष के साथियों को मौका मिला था, ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में इनकी क्या सोच थी, इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं, इनका कहना था कि गांव के किसी भी किनारे से अगर कोई तार गुजर

जाए, तो मान लिया जाता था कि वह गांव विद्युतीकृत हो चुका है - यह इनके विद्युतीकरण की डेफिनिशन थी। आज आप देखें कि विद्युतीकरण के क्या मानक बनाए गए हैं - शहर में बिजली, देहात में बिजली, गांव में बिजली, घर में बिजली - हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। बिहार में इसके तहत बहुत तेजी से काम चल रहा है। वहां 'सौभाग्य योजना' के तहत 4 करोड़ लोगों को कनेक्शन देना है, हर घर को मुफ्त कनेक्शन देना है। आप सोच सकते हैं कि इससे कितना सामाजिक परिवर्तन आएगा! पहले क्या होता था - बिजली न रहने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, 6-7 बजे के बाद पढ़ नहीं सकते थे। आज जब बिजली है, तो बच्चे जब तक इच्छा हो, पढ़ते हैं। उनके जितने दूसरे काम हैं, उन्हें भी करते हैं। इसका बहुत अनुकूल प्रभाव समाज पर पड़ा है।

मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जहां देश के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाए जा रहे हैं, गरीब घरों में आप गैस कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, बिहार में जितने हमारे ग्रामीण इलाके हैं, कस्बे हैं, वहां हर घर के पास तक पक्की गली और पक्की नाली की निर्माण किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पर भी केन्द्र सरकार को गौर करना चाहिए और पूरे देश के स्तर पर, कम-से-कम 70 साल बाद तो लोग बिना पैर में कीचड़ लगे, अपने घरों में प्रवेश कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हर घर में शुद्ध पेयजल भी मिलना चाहिए। बिहार में 'हर घर नल जल योजना' है। आप जानते हैं कि देश में पेयजल की कितनी बड़ी समस्या है! कहीं-कहीं गंगा के जल में भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड मिलता है, जिससे लोगों में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जब पाइप से वाटर सप्लाई करते हैं तो लोगों को स्वच्छ पानी

मिल रहा है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। यह बहुत अच्छी योजना है, जिसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।

(1T/DS द्वारा जारी)

DS-DPS/4.15/1T

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत)** : महोदय, आप किसान के बारे में देखें। किसान के बारे में जो घोषणा की गई है कि उनकी लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाएगा, उसमें मेरा एक ही सुझाव होगा कि अब तक की हमारी पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी रही है, वह प्रोडक्शन बेस्ड रही है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और वह एमएसपी से भी लिंक्ड रही है। इसमें पूरे के पूरे बदलाव की जरूरत है। अब हमें पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है, उसमें किसान को सेंटर में रखना है कि कैसे प्रति हेक्टेयर किसानों को मिनिमम आमदनी की गारंटी की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो CACP है, जो कि कॉस्ट का निर्धारण करती है, उसका नाम बदला जाए और उसका मैण्डेट भी बदला जाए। उनको बताया जाए कि आज आप सब जगह सब चीज़ों पर मिनिमम गारंटी देते हैं। आप "मनरेगा" में भी 100 दिनों की मज़दूरी की गारंटी देते हैं और 250 रुपये से 300 रुपये तक देते हैं। इस प्रकार, उनके लिए 25,000 से 30,000 रुपये गारंटेड हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, उनके लिए भी आप मिनिमम वेतन फिक्स करते हैं, तो फिर किसानों ने ऐसा

क्या अपराध किया है कि उनके लिए प्रति हेक्टेयर मिनिमम गारंटी नहीं होनी चाहिए? आप समझ लें कि जब किसान काम करता है, तो वह किसी से कम काम नहीं करता। इसलिए आज हम लोगों का पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए। एमएसपी के लिए जो फॉर्मूला बना, वह ठीक है, लेकिन हम लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए कि किसानों को साल भर में प्रति एकड़ कम से कम 20,000 रुपये से 25,000 रुपये की आमदनी की गारंटी कैसे हो, तब जाकर उनको लगेगा कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ...(समय की घंटी)... मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)** : आपका एक मिनट का समय और है।

**कई माननीय सदस्य** : सर, इनको बोलने दिया जाए। ...(व्यवधान)...

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह** : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आठवें साल में हूँ। चूंकि मेरे ऐसे नेता रहे, जिन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए! मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)** : ठीक है, बोलिए।

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह** : सर, मैं कल टीवी पर गुलाम नबी आज़ाद जी को सुन रहा था। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और आज भी जो मुद्दा उठा, उसको मैं सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने राज्यपाल के पद की बात उठाई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ये लोग अभी बाहर चले गए हैं, लेकिन ये जहाँ भी हों, सुन लें। इन लोगों को याद करना चाहिए कि 21 मई, 2005 को इन्होंने बिहार में क्या किया था। मैं आपको बता दूँ कि फरवरी, 2005 में बिहार में चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ किसी को मेज़ॉरिटी नहीं मिली थी। वहाँ सरकार नहीं बन पाई थी, प्रयास चल रहे थे। उसी बीच, एक पार्टी में

डिवीज़न हुआ और उस पार्टी के लोग समर्थन में आ गए। वहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही थी। उस समय के इनके जो राज्यपाल थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। वे 21 तारीख की आफ्टरनून में दिल्ली रिपोर्ट भेजते हैं, जिसके बाद दिल्ली में रात में कैबिनेट बैठती है। उस कैबिनेट की बैठक में आधी रात को निर्णय होता है कि वहाँ की असेम्बली को भंग कर दिया जाए। उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी रूस में थे, उनको फैक्स किया गया, वहाँ से उनका आदेश दो घंटे में मँगवाया गया और फिर बिहार विधान सभा को भंग कर दिया गया। अब ये गवर्नर की बात करते हैं! इन्होंने क्या किया था? सर, उसके बाद, कोर्ट ने अक्टूबर में फैसला दिया। उस फैसले को ये पढ़ लें, इनके पास वकील भरे हुए हैं। कोर्ट ने फरवरी में भी फैसला दिया, उसको भी ये पढ़ लें कि उसमें क्या है।

वर्ष 1984 को याद कर लीजिए कि इन्होंने कश्मीर में क्या किया था। ये पढ़ लें, ये सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं। वहाँ लोगों को तोड़ने के लिए किस तरह से आईबी के बैग में रुपये भेजे गए थे? वह किसके पास भेजा जाता था? गवर्नर के पास; और आज इनको मिर्ची लग रही है! यह कोई बात होती है! इसके बाद, इन्होंने कल क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। इनको सरदार पटेल के बारे में बड़ी चिन्ता हो रही है। सरदार पटेल की सन् 1950 में डेथ हो गई। सन् 1952 से चुनाव शुरू हुए, लेकिन वे इनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाए, अच्छा हुआ। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि सरदार पटेल के साथ इन लोगों ने क्या किया। सन् 1954 में पहली बार यहाँ "भारत रत्न" दिया जाना शुरू हुआ। वह तीन लोगों को दिया गया, जिनमें सी. राजगोपालाचारी नम्बर वन थे।

पटेल साहब का नम्बर कब आया? वर्ष 1991 में, 25वें नम्बर पर और वह भी तब, जब य पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखरजी प्रधान मंत्री थे।

(1यू/एमसीएम पर जारी)

KSK-MCM/4.20/1U

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत) :** 1955 में पं0 जवाहर लाल नेहरू जी ने छठे नम्बर पर भारत रत्न पा लिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पा लिया। अब आप आ जाइए 1991 में, पटेल साहब से ऊपर ही 24वें नम्बर पर राजीव गांधी जी ने पा लिया। आपने सरदार पटेल जी को कहां पहुंचा दिया, आपने सोचा ही नहीं कि इनको भी भारत रत्न देना चाहिए। एक समय था जब कौन थे? गांधी, जवाहर लाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी, आपने नहीं दिया उनको। आज आप भूल रहे हैं। हम तो भाजपा के लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि कम से कम 'Run for Unity' तो कराया सरदार पटेल के नाम पर। गुजरात में इनकी बड़ी भारी मूर्ति बन रही है, लेकिन ये क्या कर रहे थे? सरदार पटेल की जब मौत हुई थी, राजेन्द्र बाबू जी के उनके साथ संबंध थे। राजेन्द्र बाबू उनकी मौत पर गए, जिस पर कितनी तकलीफ हुई उस समय के प्रधान मंत्री को। मानवता की पुकार थी, उस समय के प्रधान मंत्री को भी जाना चाहिए था, लेकिन वे गए नहीं। आज आप देख लीजिए कि एक परिवार के तीन-तीन प्रधान मंत्रियों की समाधि यमुना किनारे बनी हुई हैं। एक तो प्रधान मंत्री नहीं थे, वे सिर्फ एम0पी0 थे, उनका भी स्थल है चौथे नम्बर पर। अब आप शुरू करिए तीनमूर्ति से लेकर, अकबर रोड से लेकर सफदरजंग रोड तक, कितने मेमोरियल बने हुए हैं? सरदार पटेल जिस घर में रहते थे, औरंगजेब रोड पर जाकर पता कर लीजिए कि उनके लिए वहां क्या है, वहां सिर्फ नर्सरी है। यह

है सरदार पटेल के बारे में आपकी सोच। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से कि आपने सरदार पटेल के लिए इतना अच्छा काम किया है, एक बड़ा मेमोरियल सरदार पटेल के लिए दिल्ली में औरंगजेब रोड पर बनाइए। अगर सरदार पटेल रहते तो आज यह कश्मीर की समस्या नहीं होती। यह जो रोज-रोज आपको तिब्बत में भुगतना पड़ता है, यह नहीं होता। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, ये बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, सरदार पटेल की लास्ट चिट्ठी है....(व्यवधान).....

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) :** अब समाप्त कीजिए।

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह :** बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। 7 नवम्बर, 1950 को उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि जो चीन तिब्बत में कर रहा है, उससे सावधान हो जाइए, लेकिन नेहरू जी क्यों पढ़ते? आप जरा समझिए कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज एक कश्मीर नहीं 565 कश्मीर होते। यह सरदार पटेल की देन है। तो बता रहे हैं कि वे याद कर रहे हैं। आज इस बार आप कहां गए थे? गए थे गुजरात और वहां पाटीदारों को कह रहे थे कि हम आपको आरक्षण देंगे। चुनाव खत्म हो गया, वहां अब कहां गए? जा रहे हैं वहां, मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं। उसकी तो चर्चा ही नही कर रहे हैं। आपको चर्चा करनी चाहिए और आप क्या चर्चा करेंगे? जब मंडल कमीशन पर आरक्षण लागू किया गया, तो उस समय के प्रधान मंत्री का भाषण सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारा National Commission for Backward Classes है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई। 2012 में जब Standing Committee on

OBCs बना, उसमें पहले दिन प्रस्ताव पारित किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कितनी खराब स्थिति रही, क्योंकि 1990 में यह बना....(व्यवधान).....

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) :** अब आप समाप्त करें।

**श्रीमती कहकशां परवीन :** यह इनकी मेडन स्पीच है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)** : मेडन स्पीच के लिए 15 मिनट होते हैं, वह भी हो गया है। अब आप बैठिए।

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह :** बस मैं अंतिम बात बता रहा हूं। 1990 में बैकवर्ड कमीशन बना। उसको क्या काम दिया गया था? बैकवर्ड जाति में कौन है, उसको जोड़ने-घटाने का कोई अधिकार नहीं। अगर किसी को शिकायत है तो कहां भेजना है, वह सिर्फ National Commission for Scheduled Castes को भेजता था। बताइए सर, आपने क्या किया? अब यहां पर लाया गया है तो तरह-तरह के विरोध कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने, वहां के जननायक ने 1978 में बैकवड़्ज़ की लिस्ट बनाई थी, जो अति पिछड़े हैं वह Annexure-I में है। पहली बार सरकार ने एक आयोग बनाया है, जो पिछड़ों में भी अतिपिछड़े हैं, उनको अधिकार देने की बात आ रही है और आजकल यह बात करते हैं पिछड़ों की। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप मुझे अब और समय नहीं दे रहे हैं, केवल एक अंतिम बात है। हम लोग चूंकि एन0डी0ए0 में हैं, मे बार-बार कहते हैं कि साहब, आप लोग बड़े कम्युनल हैं, समाज में polarise कराते हैं।

(1W/SC पर जारी)

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमागत)** : मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप याद करिए, 1984 में चुनाव हुआ था और 1985 में शाहबानो का जजमेंट हुआ। उस समय क्या स्थिति थी? इसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि हम लोगों की तुष्टिकरण की नहीं, सशक्तीकरण की नीति होनी चाहिए। उस समय क्या किया गया? उनके लिए तो पूरा का पूरा शाहबानो का अमेंडमेंट 40 दिन के अंदर ला दिया और जो सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला था, उसको रोक दिया। हिन्दुओं के लिए क्या किया? मैं उस समय फैज़ाबाद के बगल में सुल्तानपुर में ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे याद है, 1 फरवरी, 1986 को ताला खोला गया। हमारे विनय कटियार जी बगल में थे। उस समय के डीएम और एसपी से पूछा गया कि अगर ताला खोल देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह फैसला हुआ, 40 मिनट के अंदर वह ताला खोल दिया गया। उस समय इतने चैनल्स नहीं थे, लेकिन उस समय भी उसकी video recording की गयी, दूरदर्शन ने live दिखाया कि देखो, यह ताला खुल रहा है। आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं! किसने उस कार्ड को खेला? उसके बाद हमारे बिहार में भागलपुर में और यूपी में मेरठ में दंगे हुए और उसी issue पर सबसे पहला दंगा हुआ, अमेठी में मुसाफिरखाने में, जहां से उस समय के प्रधान मंत्री थे। इस प्रकार आपको तो जब मौका मिला तो आपने सोचा कि शाहबानो के केस में इस तरह का मामला कर दें और उधर ताला खुलवा दें तो सब खुश हो जाएंगे। एक बार जब आप Pandora's box खोलते हैं तो आपको पता नहीं है कि क्या होगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)** : ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अगला नाम लूंगा।

**श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह** : इसलिए ये जो बार-बार कहते हैं, इसको खत्म करना चाहिए और सब लोगों को मिलकर इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसमें सबका विकास हो सके। यही हमारे राष्ट्रपति जी का कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

**SHRI SWAPAN DASGUPTA (NOMINATED):** Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak for, I don't know how many minutes. …(interruptions)… Okay, 15 minutes; that is extremely generous because normally we, the Nominated Members, are somehow the pariahs of this place, more noted for our absence than our presence, and, I hope, at least, by making some intervention, we can redeem the situation.

Sir, President's speech is a very unique institution. It is an occasion when the Government spells out its achievements, spells out its future programme, and, Sir, it is less a vision of the President and more a vision of the Government. There is also a unique institution called a discussion on the President's speech, which is more about what the President did not say rather than what the President said, and, I think, we have seen a lot of that in this debate. We have seen two very distinct types of narratives which have come out. If some of my friends in the ghost benches are to be believed, India is going through its darkest phase; democracy has collapsed, phones are being trapped; all the schemes are being stolen, at

least, if not in content, certainly, in name. If my friend from the Trinamool Congress is to be believed, there is nothing glorious about India. He cited a lot of statistics to show how in the realm of health care, how in the realm of poverty and everything, India is still very much lower.

Now, Sir, there is a lot, we agree, which needs to be done in this country. I think, everybody across all sections of the House will agree that only a beginning has been made in making what might be called a 'New India'. Neither would I spell out much about the programmes that have been made as far as the Government is concerned, some of it is being spelt out in great details, nor am I going to go into what the Mover of this Motion, Shri Amit Shah ji, spoke about how the *janadesh* will necessarily endorse it. Those are matters which will be spoken about, and, those are matters which will be discussed at length in the coming year.

(Contd. By SK/1X)

SK/1X/4.30

**SHRI SWAPAN DASGUPTA (contd.)**: I just want to spell out two things which I think mark out this Government from whatever has happened in the past. The first, Sir, is a very important thing. People talk about jobless growth. I think there is one area of unemployment which is very, very marked, at least, in the city of Delhi, and that is the unemployment of a

category of people who used to survive and prosper, who I call *'dalals'*. The *dalali* culture which once defined Delhi, which once defined the political system, has been thrown out today. This is not to say that political corruption has ended. This is only to say that today India has made a certain stride forward in actually showing that we too can be law-abiding, we too can be compliant in whatever we do.

Sir, demonetization exercise of November, 2016 was wrongly criticized by many distinguished economists. There were two reasons why they criticized it. The first was that they could find no precedent in this, as it had not been done in the past. That was one of their main criticisms. Wherever it had been done, it had been done in destroyed, war-ravaged economies and not in a normal-functioning economy. The second issue is that this is a disruption, that India was chugging along in one direction and you suddenly put in this great disruption. Now the point about this is that the economists were right but they did not look into one thing that a political economy is not defined by the GDP alone. There is also a factor called 'ethics'. There is also a factor called 'morality'. There is also something called a healthy civic culture. The most important thing about the demonetization which I come to is that for the first time you created a system whereby certain impediments were created, institutional obstacles were created for the

generation of what we call black money, the parallel economy. That was what was hit at hardest. Sir, you have a situation where between November, 2016 to now, 1.8 million additional taxpayers have been added for direct taxes. These are the figures which are not being contested. Does it mean people suddenly found oil? Was there a sudden burst of oil economy? Did they suddenly strike gold? Or, was it because you have created an environment where people actually today want to pay tax perhaps because there is a *danda*, perhaps because the tax rates are lower? But it was not there before. Why didn't the economist talk about it then? This Government has actually created a situation where those who paid honestly, can have a sense of relief today because the burden is not going to be on them alone. I think it is that dispersal, it is that widening of the net today which has made it possible for people to actually believe that taxes can be brought down, and this is a very important point, Sir.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL)**: Your time is eight minutes.

**SHRI SWAPAN DASGUPTA**: Yes, Sir. I think I can have a couple of minutes more with the degree of generosity on your part.

Sir, therefore, when we talk about 24,800 crores of undisclosed income which has been unearthed, we are talking about a huge thing. We

are talking about a re-definition of the larger civic culture. To my mind, this is one of the biggest achievements, and this is a war which has just begun.

(Contd. by YSR/1Y)

YSR-GS/4.35/1Y

**SHRI SWAPAN DASGUPTA (CONTD.)**: If you let go now, you will go back to the old situation. So, it has to be persevered and kept on.

Sir, the second point that I want to make is this. When we were young and used to waste food or we were profligate in our spending, there used to be a saying कि कम्पनी का माल, पानी में डाल। That referred specifically to Government expenditure. इसका कोई माँ-बाप नहीं था। गवर्नमेंट का पैसा चलो, जो मर्जी करो। Today, you have introduced a culture whereby each paisa of the Government is accountable. Why is it, Sir, that we are saying that Rs. 57,000 crore has actually been saved on account of Direct Benefit Transfer (DBT)? Why is it that we are not celebrating the fact that 2.3 crore fake ration cards and three crore fraudulent LPG connections have been unearthed? This is a saving. This is a saving of the people who have paid taxes. It affects everybody. It is not merely about the people who pay income tax. It is also about the people who pay indirect taxes. It is a culture of awareness. I sometimes in the Central Hall talk to some of my ministerial friends who travel overseas. One thing which is marked about them is that

how they have been instructed quite firmly, "Don't spend any nights; where there is a connection, take it." It is quite taxing on their part. The larger point which I want to emphasise is that we have today a political culture which is growing and I think this is a very healthy trend whereby people's money is treated as sacrosanct and people are taught that it helps to be compliant and this is helping shape India's larger image. The image of India as a wasteful place, as a place which's inherently corrupt..

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल)** : धन्यवाद, अब आप समाप्त करिए।

**SHRI SWAPAN DASGUPTA:** That, at least, is being broken. Thank you very much, Sir, for giving me the time.

(Ends)

**श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा)**: उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद इसलिए भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो 45 मिनट का भाषण दिया, वह केवल मातृभाषा हिन्दी में दिया और उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपनी पार्टी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। इससे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी को और भी बढ़ावा मिलेगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में, अपनी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का वर्णन किया। इसके साथ ही साथ, उन्होंने दो विशेष मुद्दे भी उठाए।

उनमें से पहला मुद्दा यह है कि भारत में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। दूसरा, जो मुद्दा है, वह तीन तलाक के संबंध में लंबित विधेयक को पास कराने का है।

जहां तक लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात है, तो इस बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। मैं चार साल से राज्य सभा का सदस्य हूं और मैं हर साल देख रहा हूं कि कहीं न कहीं स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। अभी पीछे पंजाब में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और गुजरात में चुनाव हुए तथा इसी साल सात स्टेटों में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि बार-बार चुनाव कराने में देश का बहुत खर्चा हो जाता है। इसमें हमारे बहुत से संसाधनों और समय की खराबी होती है और इससे हमारा विकास भी प्रभावित हो जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव इकट्ठे हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है और यह देश के हित में भी रहेगा। परन्तु मुझे शंका है कि यह किस प्रकार से हो सकेगा, क्योंकि हमारी विधान सभाओं में बहुत अंतर है, जैसे पिछले साल पंजाब विधान सभा का चुनाव हुआ और अभी गुजरात का चुनाव हुआ।

(HMS/1Z पर जारी)

BHS-HMS/1Z/4.40

**श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) :** अब गुजरात में तो बी0जे0पी0 की सरकार है, तो ये उनको मना लेंगे कि चुनाव इकट्ठे करा दें, परंतु पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, ये उन्हें कैसे मना पाएंगे? हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। यह हो सकता है, लेकिन इस

के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा और मैं समझता हूं कि अभी से इस बारे में काम करना होगा।

दूसरी बात, तीन तलाक से संबंधित है। मैं इस से सहमत हूं और यह बिल शीघ्र ही पास होना चाहिए, परंतु इस में चिंता की बात यह है कि तीन तलाक बिल में जो सज़ा का प्रावधान है, उस में शंका यह व्यक्त की जा रही है कि जब उस व्यक्ति को सज़ा होगी, तो उस के परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा? महोदय, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इंसान गलतियों का पुतला है। यहां कोई भी perfect या पूर्ण नहीं है। अगर कोई पूर्ण है, तो भगवान है, वाहे गुरु और अल्लाह है। इसलिए अगर इंसान तीन तलाक की गलती करता है, तो उसे एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वह गलती करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ संशोधनों के बाद इस बिल को सरकार जल्दी पास करा सकती है और मेरा इस बिल को पूरा समर्थन रहेगा।

महोदय, जहां तक उपलब्धियों की बात है, मैं इस बात से hundred percent सहमत हूं कि देश ने आजादी से लेकर अब तक बहुत विकास किया है और इस विकास में इस सरकार का भी योगदान है और इस से पहले रही सरकार का भी योगदान रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस विकास के साथ-साथ हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है - स्कूल खोले हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, बड़े कॉलेज खुल रहे हैं और उन में पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, परंतु

इस के साथ-साथ चिंता का विषय यह है कि हमारा शिक्षा का स्तर down हो गया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमारे विद्यार्थी की सहनशीलता कम होती जा रही है। उस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और वह हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। पिछले दिनों रेयान स्कूल के एक विद्यार्थी ने अपने ही सहपाठी प्रद्युम्न की हत्या कर दी। इस के बाद पिछले दिनों यमुनानगर में स्वामी विवेकानंद स्कूल है, जिस में 12वीं के विद्यार्थी ने अपनी महिला प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरा मामला मैं बता रहा हूं - हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक झांसा गांव के बच्चों में एक किस्म के गलत संस्कार पैदा होते जा रहे हैं। वहां दसवीं की लड़की और बारहवीं कक्षा के लड़के में आपस में प्रेम प्रसंग हो गया और बाद में उन दोनों को मार दिया गया। इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा अन्यथा आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा?

महोदय, इस के बाद मैं खेती पर आता हूं। आज हमारी खेती का बहुत विकास हुआ है। वर्ष 1966 में जब हमारे यहां विदेशों से अनाज मंगाया जाता था, आज सब से ज्यादा हमारा किसान मेहनत करता है। वह सुबह 6 बजे से लेकर रात तक अपने खेतों में मेहनत कर अन्न उत्पादन करता है और सारे देशवासियों का पेट पालता है। हमारे देश के किसान का हरित क्रांति लाने में, श्वेत क्रांति लाने में, पीली और नीली क्रांति लाने में बहुत अहम योगदान रहा है, परंतु आज किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है। यह बहुत ही चिंता का विषय है और अगर इस तरफ जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सारी कृषि चौपट हो जाएगी और किसान बरबाद हो जाएगा।

फिर जिस प्रकार 1966 में हम बाहर से अनाज मंगवाते थे और वह भी घटिया किस्म का होता था, उसी प्रकार का अनाज हमें विदेश से मंगवाना होगा। महोदय, आज खेती किसान के लिए घाटे का सौदा बन गया है क्योंकि आज खाद महंगी हो गयी है, दवाइयां महंगी हो गयी है, बीज महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। इस के अलावा नील गाय भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इस की तरफ भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, सरकार कहती है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। धन्यवाद, अगर ऐसा हो जाए, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, परंतु आपका आर्थिक सर्वे यह बता रहा है कि पिछले 3 सालों से किसानों की आर्थिक स्थिति stable रही है।

(2 ए/एएससी पर जारी)

ASC- RL/2A/4.45

**श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) :** वह तो बिल्कुल टिकी हुई है। किसानों की आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं है। अभी सरकार ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य डेढ़ गुना दिया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि सरकार किसानों को डेढ़ गुना मूल्य दे नहीं सकती, तो उस एफिडेविट का क्या होगा? यह भी एक सोचने की बात है। एक चिंता का विषय और भी है। मुझे एक कृषि के डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की बीमारी हमारी फसलों में भी होती है। उसने कहा कि कैंसर की बीमारी मोस्ट्ली टमाटर और भिंडी की फसल में होती है। किसानों को तो पता ही नहीं होता है कि उनमें कैंसर की बीमारी कैसे होती है। सरकार के लिए यह भी एक सोचने का विषय है। जब टमाटर और भिंडी में कैंसर हो गया और जब वह मार्केट में आएगा,

जब उसको लोग खाएंगे, तो फिर उनको भी निश्चित रूप से कैंसर हो जाएगा। यह भी एक चिंता का विषय है, इसलिए सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। इसके ऊपर भी रिसर्च करनी होगी कि किस प्रकार से टमाटर और भिंडी में कैंसर होता है।

आप देखेंगे कि शहरों में बहुत विकास हुआ है और इसी प्रकार यदि हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है। इसका भी बहुत विकास हुआ है, यहां पर बहुत बिल्डिंग्स बनी हैं और बहुत सड़कें बनी हैं, लेकिन जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, तो देखते हैं कि यहां की हवा दूषित है। आज दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। इसके प्रदूषित होने के बहुत से कारण हैं। यहां पर ज्यादा व्हीकल्स हैं, पेड़ों की कटाई है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है, तो हमें यहां पर ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे और जो पेड़ लगे हैं, उनको भी बचाना है।

मैंने बंदरों के बारे में पहले भी कहा है कि दिल्ली में बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मैं साउथ एवेन्यु में रहता हूं। वहां पर भी काफी बंदर हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि जब बंदर किसी एमपी को काट लेगा, तो बड़ी परेशानी होगी। यह बहुत ही चिंता का विषय है। वहां पर जितने भी पेड़-पौधे लगे हैं, ये बंदर न तो उनको उगने देते हैं और उनको तोड़कर उजाड़ने का काम करते हैं। हमें हर रोज बंदरों द्वारा तोड़े गए सामान को उठवाने के लिए सामान उठाने वालों को बुलवाना पड़ता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि दिल्ली को बचाना है, तो यहां के प्रदूषण को ठीक करना है और बंदरों ने जो आतंक मचा रखा है, उसको ठीक करने लिए सोचना पड़ेगा। यदि सरकार ने समय रहते इसके बारे में नहीं सोचा, तो फिर यदि किसी एमपी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाएगी, मुझे लगता है तभी सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी।

महोदय, मैं मिलावट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। हमने काफी फ्रूट्स पैदा किए हैं, सब्जियां पैदा की हैं और अनाज भी पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां अनाज भी ज्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन जो हमारी खाने-पीने की चीजें हैं, वे सब दूषित हो गई हैं। आज हमारी सब्जियां ठीक नहीं है, फल-फ्रूट्स ठीक नहीं हैं और अनाज भी ठीक नहीं है। फसल में दवाई डालना किसान की मजबूरी है। किसान पशुओं के लिए जो बरसीम बोता है, वह आज तक उसमें कभी दवाई नहीं डालता था, परन्तु आज किसान को मजबूरी में पशुओं के चारे में भी दवाई डालनी पड़ती है। जब उस पेस्टिसाइड के चारे को पशु खाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि पशु कैसा दूध देगा। आज हम 60 परसेंट नकली दूध पी रहे हैं। आज दूध की डिमांड ज्यादा है, तो फिर दूध कहां से आएगा? आज हम मजबूरी में नकली दूध पी रहे हैं। आज हमारी सब्जियां भी दूषित हैं। हमारे खेतों में जो अनाज पैदा होता है, अगर उसकी क्वालिटी चैक की जाए, तो हो सकता है यह भी हमारे खाने लायक न हो, लेकिन हम इसको मजबूरी में खा रहे हैं। इसी कारण हमारे देश में आज बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो देश में बीमारियां बढ़ती जाएंगी। फिर तो एक ही इलाज होगा कि देश में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाएं, ताकि लोगों का सही से इलाज हो सके। इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, तो ज्यादा पैसा कहां से आएगा, यह चिंता का विषय है।

सरकार ने केन्द्र में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया है, तो मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह तो ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।

(LP/2B पर जारी)

LP-DC/4.50/2B

**श्री राम कुमार कश्यप (क्रमागत) :** हमें ओबीसी वर्ग में अब राजनैतिक आरक्षण भी चाहिए। किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज के भाग्य का फैसला कहाँ होता है? उसके भाग्य का फैसला या तो पार्लियामेंट में होता है या विधान सभा में होता है। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की विधान सभा में, पार्लियामेंट में मौजूदगी नहीं होगी, तो क्या पिछड़े वर्ग के लोग उठ सकते हैं? उनके भाग्य का फैसला हो, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके साथ-साथ ओबीसी वर्ग को, इस पिछड़े वर्ग को राजनैतिक आरक्षण भी दिया जाए। इसके बिना इनका विकास होना असंभव है। अंत में मैं आपको धन्याद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद-जय भारत।

(समाप्त)

**उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) :** आपका भी धन्यवाद कि आपने समय से पहले समाप्त कर दिया। श्री आर.एस. भारती, अनुपस्थित हैं, श्री मेघराज जैन।

**श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश) :** आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है। संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर का मत था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के

बिना राजनैतिक लोकतंत्र अधूरा है। उनकी इसी मूल भावना को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए स्वच्छता की बात कही। देश में स्वच्छता हो, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया, लेकिन एक दूसरे स्वनाम धन्य नेता ने उसका मज़ाक उड़ाया। यह उनकी आदत है, क्योंकि वे और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हर बात पर मज़ाक उड़ाते हैं। उन्होंने मज़ाक उड़ाया, वे देश भर में भाषण करते फिरे कि प्रधान मंत्री ने क्या किया, देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, उन्होंने ऐसा पूरे देश में भाषण दिया, पर देश की जनता ने उनकी, प्रधान मंत्री जी की इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। देश के बड़े-बड़े कलाकार, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी, किसान, महिलाएँ, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों ने भी उस अभियान को देश में एक आंदोलन का रूप दिया और आज पूरे देश में, आप जिधर भी जाइए, आपको सफाई दिखेगी। यानी लोगों में सफाई के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उनको समझ में आया कि साफ-सफाई रहने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारा वातावरण ठीक होगा, हमारा पर्यावरण ठीक होगा, इसलिए आज देश में सफाई हुई। जो नेता इस तरह की बात करते थे, इस सफाई अभियान के कारण उनकी बोलती बंद हो गई। अभी कल उन्होंने एक भाषण दे दिया कि प्रधान मंत्री की बात को कोई महत्व नहीं देता है। उनको पता है कि इस देश में - कल जैसे पार्टी अध्यक्ष, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता हुए हैं,जिनके कहने पर देश में 1 करोड़, 30 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। क्या कोई सब्सिडी छोड़ता है? आदमी एक पैसा

छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन इतने लोगों ने देश के अंदर अपनी सब्सिडी छोड़ी है। यह इस बात को दर्शाता है कि उस नेता पर उस देश की जनता का कितना विश्वास है, उस नेता के प्रति जनता के मन में कितनी श्रद्धा है कि उनके कहने से उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन उस नेता का मज़ाक उड़ाया जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि इनकी कोई सुनता नहीं है। आज यह स्थिति बन गई है कि जनता ने जिनको सत्ता से हटा दिया, सत्ता से बाहर होने के बाद उनके अंदर खीज पैदा हो गई है और इसलिए वे किसी भी सही बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने देश में मनरेगा लागू किया, उसके लिए खूब शोर मचाया। उसके लिए बताया कि हमने गरीबों के लिए यह किया है। आपने जरूर किया है, आपने गेंती, फावड़ा उनके हाथ में पकड़ाया और उनसे कहा कि जाओ, मिट्टी खोदो। उनको जो पैसा दिया जाता था, वह भी आधा-अधूरा पैसा मिलता था। वे खून-पसीना बहाते थे, लेकिन उनको आधा पैसा मिलता था और आधा पैसा बीच में खा जाते थे। आज उनको आधार से लिंक करने से, खाते खोलने से उनको बराबर पैसा मिल रहा है। उनको इसके लिए भी आपत्ति है। इसके लिए बड़े-बड़े वकील कोर्ट्स में जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि साहब, इसको आधार से मत जोड़ो, आधार हमारी निजता खत्म कर देगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन-सी निजता खत्म हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचार की निजता खत्म हो जाएगी? आपकी कौन-सी निजता थी? आपकी कौन-सी गोपनीयता थी? आज जो हज़ारों, करोड़ों रुपये बचे हैं, आप जो यह भ्रष्टाचार करते थे, उससे बचे ये पैसे आज देश के विकास के काम आ रहे हैं।

(2c/klg पर जारी)

KLG-KR/2C/4.55

**श्री मेघराज जैन (क्रमागत)**: आदरणीय आज़ाद साहब ने कहा कि आप हमारी योजनाओं की रीपैकेजिंग करते हैं। आज वे यहां सदन में नहीं हैं, चले गए, बाहर कहीं सुन रहे होंगे। आदरणीय आज़ाद साहब, हम रीपैकेजिंग नहीं करते हैं। आपकी योजनाएं थीं, आपने बनाईं, उनका ढिंढोरा पीटा, उनका लाभ लिया, चुनाव में जीत गए और बाद में उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। हमने उन योजनाओं को, जो आपकी हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, हमने उनको पुनर्जीवित किया, उनमें प्राण फूंके, देश में उनको लागू किया और उन योजनाओं के कारण देश में आज लोगों को लाभ मिल रहा है। आज गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला सम्मान से अपने घर में जाते हैं और उन योजनाओं से लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का विकास कर रहे हैं।

महोदय, किसानों के लिए कृषि बीमा योजना है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हमने बिना ब्याज के किसानों को ऋण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने तीन लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देने की योजना बनाई। किसान ऋण लेते हैं, वापस देते हैं और उनको ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। अब अगर किसी ने एक लाख रुपए का ऋण लिया है, तो ब्याज भी मत दो और एक लाख रुपए की जगह नब्बे हजार रुपए जमा कराओ, ऐसी योजना किसानों के लिए लागू की गई है। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना शुरू हुई, जिससे किसान की जमीन सिंचित हुई, उसकी आमदनी बढ़ी है। डेयरी उद्योग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन से आमदनी और जैविक खेती से खेत में लागत मूल्य कम होने जैसे उपाय किए गए। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश के गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला, कृषक और मजदूर की सेवा का ध्यान किया

है, जिसे पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री जी और उनके सभी साथी जी-जान से जुटे हुए हैं। अब अगर ये लोग विरोध करते हैं, तो क्या करें? खंभा नोच रहे हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत दस करोड़ लोगों ने चार लाख करोड़ का ऋण लिया है, जो उनका स्वीकृत हुआ है। इनमें तीन करोड़ लोगों ने पहली बार ऋण लिया है। हमारे आज़ाद साहब ने कहा कि 41,000/-रुपए से ज्यादा ऋण मिलता ही नहीं है। आदरणीय, वह कोई माल्या जैसों के लिए योजना नहीं है, यह योजना गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है। यह उन आदिवासियों के लिए है, उन गरीबों के लिए है, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रह कर काम करते हैं, उनके लिए है। जो टीन-टप्पर ठोकते हैं, जो छोटे-मोटे मैकेनिक होते हैं, जो गाड़ियां सुधारते हैं, उनके लिए यह योजना है। उन गरीब लोगों ने ऋण लिया, क्योंकि छोटे गरीब आदमी को इतना ही ऋण चाहिए। पहले क्या होता था कि वह किसी साहूकार के पास जाता था, उसके पास जाकर दो सौ रुपए, पांच सौ रुपए, हजार रुपए लेकर आता था और उसके बदले साहूकार को इतना देना पड़ता था कि अगर दो सौ रुपए लेकर आया था तो शाम को उसे दो सौ रुपए के साथ बीस रुपए देने पड़ते थे। उसकी जो खून-पसीने की मेहनत थी, वह साहूकार को देनी पड़ती थी। आज उससे वह मुक्त हुआ है। गरीब रिक्शे वाला, ठेले वाला, चाय बनाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पकोड़े बनाने वाला, इन सब लोगों को इससे ऋण मिला है और इसी प्रकार कई महिलाओं को ऋण मिला है, जिससे वे लोग अपना जीवन-स्तर सुधार रहे हैं। इस पर भी आपत्ति है। अगर पकौड़े बेचना मजदूरी है, तो फिर भीख मांगना भी मजदूरी है। अब भीख मांगना ओर पकौड़े बेचना, एक आदमी कितनी मजबूरी में ऐसा करता है, शायद उनको नहीं मालूम है। एक छोटा आदमी पकोड़े बेचता है, वह रातों-रात तो करोड़ों

रुपए का बिजनेस नहीं कर सकेगा, धीरे-धीरे अपना विकास करेगा। रोज समाचार-पत्रों में पढ़ने में आता है कि एक व्यक्ति ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और धीरे-धीरे आज वह कहां से कहां पहुंच गया है। अब पकोड़े बना कर उसे बेच कर, मूंगफली बेच कर, सब्जी बेच कर, ठेला चला कर, परिश्रम करके अगर कोई रोज दो-चार सौ रुपए कमाता है और शाम को जब घर जाता है तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े सुख के साथ अपने परिवार के साथ बैठकर अपने परिश्रम की रोटी खाता है, उसको इससे संतोष प्राप्त होता है। वह भी इनको पसंद नहीं है। उसको भीख का दर्जा दे दिया। जो आपने मनरेगा चलाया था, जो मजदूरी करने के लिए लोगों को गेती, फावड़ा दिया था, उसमें उसको दो सौ रुपए मिलते थे, वह क्या भीख थी?

(2डी/एकेजी पर जारी)